साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 14-20 अक्टूबर 2024 वर्ष-10, अंक-26

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

बैट्री का दम फूला: ट्रेनिंग ली, काम भी मिला, पर अब टूटने लगे सपने

ड्रोन दीदियां नहीं भर पा रहीं उड़ान

» कहीं पांच, कहीं 15 मिनट में ही बैट्री की सांसें उखड़ने लगीं

» दो स्पेयर बैट्री देने की थीं योजनाएं, लेकिन सब ठंडे बस्ते में

भोपाल। जागत गांव हमार

मप्र की ड्रोन दीदियां आत्मनिर्भरता की उड़ान नहीं भर पा रही हैं। उन्हें सशक्त बनाने और खेतों में उर्वरक का छिडक़ाव कर आय का जरिया बनाने के लिए जो ड्रोन दिए गए, लेकिन 5 से 7 मिनट में ही बैट्री का दम फूल जाता है। ऐसे में पांच एकड़ के खेत में उर्वरक का छिडक़ाव करने के लिए कई बार बैट्री चार्ज करना पड़ रहा है। 15 किलोग्राम वजनी ड्रोन में घंटेभर उड़ान के लिए दो बेट्री लगाई गई है। ड्रोन देने के दौरान कंपनियों ने दावा किया था कि दोनों बैट्री के फुल चार्ज होने पर आधे-आधे घंटे बैकअप मिलेगा। ड्रोन ऊंचाइयों से खेतों में दवा छिडक़ेगा। लेकिन अब दोनों बैट्री की सांसें उखड़ रही हैं।

कहीं महज कहीं 5 से 7 मिनट तो कहीं 12-15 मिनट की उड़ान के बाद ही ड्रोन जमीन पर आ जा रहा है। ऐसे में किसानों से ऑर्डर लेने के बाद भी ड्रोन दीदियां छिडक़ाव नहीं कर पा रहीं। उन्हें छिडक़ाव पर मिलने वाले प्रति एकड़ 300 से 500 रुपए से भी हाथ धोना पड़ रहा है। दीदियां आत्मनिर्भर होने की बजाय बैट्री और सरकारी रहमोकरम पर निर्भर हो गई हैं। आत्मनिर्भरता से निर्भरता की ओर मुडऩे पर विवश हुईं प्रदेश की ऐसी ही कुछ ड्रोन दीदियों की दास्तां बताती 'जागत गांव हमार' की विशेष रिपोर्ट।

ऑर्डर तो खूब मिले, पर साथ नहीं मिला

सीधी जिले के सिहावल तहसील के खोरवा टोला के लक्ष्मी स्व सहायता समूह को कृषि में नई तकनीक को बढ़ावा देने, लागत कम करने में भागीदारी के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन योजना के तहत चुना। समूह सचिव मनीषा कुशवाहा को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग इंदौर के प्रेस्टीज कॉलेज में शोरिंग एरोटेक कंपनी के विशेषज्ञों ने दी। फिर नोएडा में दूसरे चरण की ट्रेनिंग मिली। समूह को शत-प्रतिशत अनुदान पर ड्रोन दिया। समूह की ओर से मनीषा ने आस-पास किसानों के खेतों में ड्रोन से उर्वरक का छिडक़ाव शुरू किया।

अब ऐसी हालत-

ड्रोन दीदी मनीषा ने बताया कि ड्रोन के साथ दो बैट्री दी थी। दोनों बैकअप नहीं दे रही। शुरुआत में ट्रायल के दौरान एक बैट्री आधे घंटे चलती थी। अब 5 से 7 मिनट ही बैकअप मिल रहा है। एक बार चार्ज करने पर दो से तीन एकड़ खेत में ही छिडक़ाव हो पाता है। इससे काम पूरे नहीं हो रहे।

कमाई घटी-

मनीषा ने बताया 150 किसानों ने ऑर्डर दिए, पर 50 के यहां ही छिडक़ाव कर सकी। बैट्री सही होती तो अधिक किसानों तक पहुंच जाती।

खास-खास-

» सब होता सही तो बड़े काम का था ड्रोन
» 15 किलो वजनी ड्रोन मिला निःशुल्क
» 4 किलो की दो-दो बैट्री
» 10 किग्रा केमिकल लेकर उड़ने की क्षमता
» 300 से 500 प्रति एकड़ हो जाती कमाई

यहां भी ऐसे हालात

सतना: 17 मिनट में ही फेल

महिला किसान साधना तिवारी को चेन्नई की कंपनी ने गरुड़ ड्रोन मिला। अफसरों का दावा था एक बार बैट्री फुल चार्ज होने पर ड्रोन 30 मिनट में 8 एकड़ खेत में छिडक़ाव कर देगा। अब ड्रोन मात्र 17 मिनट ही काम कर रहा है।

रीवा:12 मिनट का ही दम

बेलहा गांव की ड्रोन दीदी सबिता विश्वकर्मा ने बताया, ड्रोन उड़ता है, पांच-छह मिनट में एक एकड़ में छिडक़ाव करता है और 12 मिनट में ही ड्रोन की सांसें फूल जाती हैं।

देवास: 15 मिनट में नीचे ड्रोन

सतवास के स्व-सहायता समूह की मंजू मस्कोले ड्रोन दीदी कहलाती हैं। शुरुआत में तो उनका ड्रोन अच्छा काम कर रहा था। लेकिन अब ड्रोन ऊंचाई नहीं पकड़ रहा। बैट्री के फुल चार्ज होने के महज 15 मिनट में ही नीचे आ जाता है। पांच मिनट तो ड्रोन को जियो फेंसिंग में ही लग जाते हैं। ऐसे में महज 10 मिनट छिडक़ाव का समय मिलता है। निर्मला राठौर भी कमजोर बैट्री का दंश झेल रही हैं।

24 करोड़ लागत की परियोजना से 8 हजार आबादी को मिला लाभ

अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर में पहुंचा हर घर नल-जल

भोपाल। अलीराजपुर जिले में महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली चंद्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) के हर घर में नल से शुद्ध जल पहुंच रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी की इंदौर इकाई द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से चन्द्रशेखर आजाद नगर में जल प्रदाय परियोजना का कार्य पूरा किया जा चुका है। नगर के 1520 से अधिक घरों को नल कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। हर घर को जल प्रदाय नेटवर्क से जोड़ने के लिए 44 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाई गई है। पानी के संग्रहण के लिए 150 किलोलीटर का ओवर हैड टैंक निर्मित किया गया हैं। इस परियोजना में हथनी डैम से जल लिया जा रहा है, जल को शुद्ध करने के लिए 1.6 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र भी स्थापित किया गया है। दस वर्षों के संचालन और संधारण के साथ इस परियोजना की लागत लगभग 24 करोड रूपये है, इससे 8 हजार से अधिक की आबादी को लाभ हो रहा है। जल प्रदाय परियोजना के पहले चंद्रशेखर आजाद नगर के रहवासी पानी के लिए बोरिंग पर निर्भर रहते थे पर अब समय पर भरपूर पानी मिल रहा है। चंद्रशेखर आजाद नगर के वार्ड क्रमांक 5 निवासी बनम सिंह का कहना है पानी घर बैठे मिल रहा है, पहले पानी की किल्लत रहती पर अब पानी समय पर आता है। कमलेश सिंह कहते है कि नल से आने वाले जल की गुणवत्ता अच्छी है, अब जल संबंधित सभी समस्याओं के निराकरण हुआ है। आजाद नगर में जल जनित बीमारियों का खतरा भी नहीं है। सपना सिंह का कहना है कि पहले पानी के लिए बाहरी स्त्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था, अब स्वच्छ एवं पर्याप्त जल घर पर ही नल कनेक्शन के माध्यम से आ रहा है।

गेहूं बोवनी का रिकार्ड 110 लाख हेक्टेयर तक बढ़ने का अनुमान

मानसून अच्छा होने से मध्यप्रदेश में टूटेगा गेहूं की बोवनी का रिकॉर्ड

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में इस बार मानसून अच्छा रहने से गेहूं का बोवनी का रिकॉर्ड भी टूटेगा। अभी तक अधिकतम 95 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हुई है। इस बार 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बढ़कर 110 लाख हेक्टेयर पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए कृषि विभाग ने खाद-बीज को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले सप्ताह से होने वाली कृषि उत्पादन आयुक्त की संभागीय बैठकों में लक्ष्य निर्धारित हो जाएंगे। प्रदेश में अकेले रीवा जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में औसत से अधिक वर्षा हुई है। इससे रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं का क्षेत्र बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 में 97.81 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोवनी हुई थी, जो 2023-24 में घटकर 92.10 लाख हेक्टेयर रह गई थी, यानी गेहूं का क्षेत्र 5.84 प्रतिशत घट गया था। यह फिर बढ़कर 95 लाख हेक्टेयर के आसपास पहुंच गया।

» चना का क्षेत्र 21 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 23.46 लाख हेक्टेयर
» सीएम ने केंद्र से खाद-बीज की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया
» पंजाब को पीछे छोड़ मध्य प्रदेश उपार्जन में देशभर में था अव्वल

उपार्जन में पंजाब को पीछे छोड़ चुका है मप्र | प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार गेहूं का उपार्जन करती है। गत वर्ष बाजार में अधिक मूल्य मिलने के कारण उपार्जन कम हुआ था। जबकि, 2020-21 में पंजाब को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश उपार्जन में देशभर में अव्वल रहा था। यहां के शरबती गेहूं की देश-दुनिया में मांग रहती है।

गेहूं का क्षेत्र बढ़ने की अनुमान

इस बार वर्षा की स्थिति को देखते हुए कम जोखिम वाली फसल गेहूं का क्षेत्र बढ़ने की अनुमान लगाया जा रहा है। मालवांचल, मध्य भारत और महाकोशल अंचल में क्षेत्र बढ़ने की अधिक संभावना है क्योंकि यहां सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता अधिक है। चना का क्षेत्र भी लगातार बढ़ रहा है। यह 2022-23 में 21 लाख हेक्टेयर था जो 2023-24 में बढ़कर 23.46 लाख हेक्टेयर हो गया। इसमें भी वृद्धि हो सकती है। रबी फसलों का क्षेत्र बढ़ने के अनुमान के आधार पर मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने भारत सरकार से अक्टूबर-नवंबर में अतिरिक्त डीएपी, एनपीके, कम्प्लेक्स और बीज की आपूर्ति बढ़ाकर करने का अनुरोध किया है।

35 हजार रुपए में बिकती है जैविक कपास की जींस

किसानों को नहीं मिल पाता है कपास का उचित मूल्य

इंदौर। जागत गांव हमार

जैविक कपास की जींस आज बाजार में 35 हजार रुपए तक मिलती है। दिनरात मेहनत कर कपास उगाने वाले किसान को उस कपास के चंद रुपए मिलते हैं। मार्केट गैप के कारण किसान को सही आय नहीं मिल पाती। जैविक कपास की बहुत अधिक डिमांड है और मालवा निमाड़ में कपास की अच्छी पैदावार है। यदि एक मंच पर किसान और इंडस्ट्री एक साथ समाधान निकालेगी तो किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। यह बातें सॉलिडारिडाड, अलायन्स ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल स्टेकहोल्डर्स संस्था के मप्र के महाप्रबंधक डॉ सुरेश मोटवानी ने बातचीत में कही। इंदौर में संस्था ने मालवा निमाड़ के किसानों के लिए ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी ने भी किसानों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस (सीआरबी) के सहयोग से आयोजित इस एक दिवसीय संगोष्ठी का विषय था 'भारत में पुनर्योजी कृषि कपास मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने में अवसर और चुनौतियां'। इस अवसर पर कपास उत्पादन एवं इसकी मूल्य श्रृंखला से जुड़े हुए विभिन्न विशेषज्ञों, स्थायी उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रबंधकों एवं कपास उत्पादन से जुड़े कृषकों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया। इसका मूल उद्देश्य है कि भारत में कपास उत्पादन के क्षेत्र में पुनर्योजी विधि को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया जा सके ताकि देश में कपास उत्पादन अर्थ व्यवस्था को स्थायित्व मिल सके।

सांसद शंकर लालवानी ने कार्यक्रम में कहा कि मध्य प्रदेश में कपास की खेती के लिए पर्याप्त संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। वर्तमान में, पारंपरिक खेती से पुनर्योजी कृषि में रूपांतरण कपास की खेती के लिए एक वरदान है। सॉलिडेरिडाड कपास किसानों के बीच पुनर्योजी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। सरकार मध्य प्रदेश में कपास का क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है। इसके मद्देनजर, हम धार जिले में 10,000 करोड़ का कॉटन और टेक्सटाइल हब स्थापित कर रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।

पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना होगा

डॉ सुरेश मोटवानी ने कहा की आज विश्व कपास दिवस के अवसर हमें याद रखना चाहिए की कपास न केवल एक फसल है बल्कि देश के लाखों किसानों एवं परिवारों के जीवन का आधार है। संस्था दो लाख किसानों के बीच काम कर रही है। पुनर्योजी कृषि को अपनाकर, हम कपास उत्पादन को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के लिए एक शक्ति में बदल सकते हैं। इससे किसानों के लिए एक स्थायी आजीविका सुनिश्चित होगी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी कृषि पारिस्थितिकी सुरक्षित एवं संरक्षित बनी रहेगी।

मिट्टी से लेकर भंडारण तक चुनौतियां

इस अवसर पर एसीआरई के प्रतिनिधि रंजीब सरमा ने कहा कि पुनर्योजी कृषि तकनीक से कपास उत्पादन के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी बदलाव लाया जा सकता है जिससे वर्तमान उत्पादन में आ रही चुनौतियों को काफी कम किया जा सकता। मिट्टी से लेकर भंडारण तक में स्थिरता सुनिश्चित करना होगी। जलवायु अनुकूल तकनीक के साथ किसानों को सशक्त बनाने और वस्त्र उद्योग के हितधारकों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के माध्यम से, हमारा लक्ष्य भारत को पुनर्योजी कपास उत्पादन में वैश्विक पटल पर अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है, जिससे हमारे किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए एक अनुकूल भविष्य सुनिश्चित हो सके।

यह वैश्विक आंदोलन बन सकता है | इस अवसर पर कार्य म को संबोधित करते हुए रिजित सेनगुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस ने कहा की विश्व कपास दिवस पर, कपास उत्पादन के भविष्य को आकार देने में स्थायी पुनर्योजी विधियों की भूमिका को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। हमारा मानना है कि पुनर्योजी कृषि लाखों किसानों की आर्थिक भलाई के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करने की कुंजी है। कपास मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देकर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत का कपास उद्योग न केवल फले-फूले, बल्कि जिम्मेदार और समावेशी उत्पादन के लिए वैश्विक आंदोलन में भी योगदान दे।

सतधरू मध्यम सिंचाई परियोजना से 670 गांव में पेयजल पहुंचाने की योजना

सात साल में भी नहीं पूरी हो पाई योजना

जल जीवन मिशन अधूरा! 111 गांव तक नहीं पहुंच पाया पानी

दमोह। जागत गांव हमार

जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सतधरू मध्यम सिंचाई परियोजना से 670 गांव में पेयजल पहुंचाने की योजना पिछले 7 साल बाद भी पूर्ण नहीं हो पाई है। वर्ष 2017 में शुरू हुई इस योजना को वर्ष 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन चार बार समय-सीमा बढ़ाने के बाद 111 गांव में अभी तक जल सप्लाई शुरू नहीं हो पाई हैं। इन गांव में पानी पहुंचाने के लिए अभी तक टंकियों का निर्माण भी पूर्ण नहीं हो पाया है। इधर जल निगम के अधिकारियों द्वारा जिन 559 गांव में पानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, उन गांव में भी नियमित रूप से पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है। हालात यह हैं कि सप्ताह में एक या दो दिन पेयजल सप्लाई हो रही है। दो माह पहले तक जल निगम के अधिकारियों का एक ही बहाना रहता था कि बांध में पर्याप्त पानी नहीं हैं और न ही पर्याप्त बिजली पहुंच रही है, लेकिन यह समस्या दो माह पहले ही खत्म हो चुकी है। इस बार हुई भारी बारिश के चलते सतधरू बांध लबालब भर गया है और अभी भी इसके गेट खुले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बिजली कंपनी द्वारा डेम के पास बनाए गए फिल्टर प्लांट पर इमरजेंसी बिजली सप्लाई लाइन डाली गई है, जिससे यहां पर बिजली निर्बाध रूप से चालू रहती है। इसके बावजूद भी जल निगम के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि सतधरू डेम से दमोह-पटेरा एवं जबेरा तेंदूखेड़ा ब्लॉक के गांव में पेयजल सप्लाई करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 600 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत की थी, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते यह योजना अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निगम के महाप्रबंधक उमेश नामदेव को कई बार फोन लगाया, लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव ही नहीं किया जाता। जब ऑफिस जाते हैं तो वह मिलने से इंकार कर देते हैं और अन्य कर्मचारियों के पास भेज देते हैं। जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है।

सप्ताह में एक दिन हो रही पेयजल सप्लाई

जल निगम द्वारा इस योजना के तहत जिन गांव में पानी सप्लाई शुरू की है, वहां पर नियमित रूप से जलापूर्ति नहीं हो रही है। शहर से से सटे ग्राम ग्राम चौपराखुर्द की आबादी 15 हजार है। यहां पर 10 लाख लीटर की पानी की टंकी परशुराम टेकरी पर बनाई गई है। इसी तरह दूसरी टंकी बरपटी पहाड़ी पर बनी हुई है, लेकिन यह टंकी पूरी नहीं भरी जा रही है। पेयजल सप्लाई करने वाले कर्मचारियों का कहना कि टंकियां पूरी नहीं भर पा रही हैं। कभी आधी टंकी भरती है और सप्लाई बंद हो जाती है। जिसकी वजह से इस क्षेत्र में दो से तीन गलियों में पानी दिया जा रहा है। जबकि यह क्षेत्र काफी बड़ा है। इधर वंसुधरा कॉलोनी, इंद्रमोहन नगर, सुरेका कॉलोनी और हिरदेपुर में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। स्थानीय निवासी आनंद तिवारी, वीरत सिंह ठाकुर, मुकुट बिहारी रघरे, दीपक जैन का कहना है कि अधिकारियों द्वारा जानबूझकर सप्लाई प्रभावित की जा रही है। पूर्व में जो अधिकारी पदस्थ थे, तब तक काम रही चलता रहा, लेकिन पिछले छह माह से सप्ताह में केवल एक बार ही पानी दिया जा रहा है। जिससे हम लोगों को आसपास के कुओं व हैंडपंपों का सहारा लेना पड़ रहा है।

अधिकारी बोले- मेन लाइन में अवैध कनेक्शन

जल सप्लाई का काम देखने वाले अधिकारी आरके कोष्टी व अतुल तिवारी का कहना है कि ग्रामीण अंचलों में लोगों द्वारा मेन लाइन से अवैध कनेक्शन कर लिए गए हैं। अकेले चौपराखुर्द, रैयतवारी में 170 अवैध कनेक्शन किए गए हैं। तीन माह पहले कनेक्शन हटाए गए थे, लेकिन फिर हो गए हैं। हम लोग अकेले कनेक्शन नहीं काट सकते। इसके लिए प्रशासन का सहयोग जरूरी है। इसकी जानकारी कलेक्टर को भी दी गई है। जल निगम के डीजीएम गौरव सराफ का कहना है कि सतधरू परियोजना के तहत 670 गांव में पेयजल सप्लाई की योजना अंतिम दौर में चल रही है। करीब 111 गांव शेष बचे हैं, जहां टेस्टिंग चल रही है। कुछ टंकियों का काम बाकी है। जो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण हो जाएगा।

वेयर हाउस एवं गोदामों की सूची पर 18 अक्टूबर तक आपत्ति होगी दर्ज

जबलपुर, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 समथज्न मूल्य में उपाजित्त की जाने वाली धान, ज्वार, बाजरा के भंडारण हेतु मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के जिला प्रबंधक द्वारा वरीयता क्रमानुसार वेयर हाउस एवं गोदामों की तैयार की गई सूची पर 18 अक्टूबर तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। वेयरहाउस एवं गोदामों की सूची का प्रकाशन जिला प्रशासन जबलपुर की वेबसाइट https//Jabalpur.nic.in पर किया गया है। सूची जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन एवं कृषि उपज मंडी कार्यालय में भी चस्पा की गई है। जिला आपूर्ति नियंत्रक एवं डिप्टी कलेक्टर कुलदीप पाराशर के मुताबिक यदि सूची में उल्लेखित वेयर हाउस एवं गोदामों के प्राथमिकता क्रम के निर्धारण के संबंध में अथवा किसी अन्य बिन्दु पर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह अपनी लिखित आपत्ति 18 अक्टूबर तक कलेक्ट्रेट स्थित जिला आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय अथवा जिला प्रबंधक कार्यालय मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन को प्रस्तुत कर सकता है।

जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि इसके पूर्व समर्थन मूल्य पर उपार्जित की जाने वाली धान, ज्वार एवं बाजरा के भंडारण हेतु वेयर हाउस एवं गोदामों की वरीयता क्रमानुसार तैयार की गई सूची पर 4 अक्टूबर तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के बाद गोदामों की रिक्तता के आधार पर जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा संशोधित वरीयता क्रमानुसार सूची का पुन: प्रकाशन किया गया है।

योजना को आगे चलाने पशु संचालनालय ने खड़े किए हाथ

राजमार्गों को कैटल फ्री करने की योजना अधर में

विभागों की बेरुखी और आपसी तालमेल की कमी के चलते योजना मूर्त रूप नहीं ले पाई

भोपाल। जागत गांव हमार

मप्र की सडक़ों और हाइवे पर गौ वंश के कारण होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं और उसमें होने वाली मौतों को देखते हुए सरकार ने गौ पेट्रोलिंग योजना बनाई थी। इसके तहत सडक़ों से गायों को हटाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था, लेकिन इस योजना की ढाई माह में ही इस कदर सांस टूटने लगी है कि इसे बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल, योजना को आगे चलाने के लिए पशु संचालनालय ने हाथ खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश की सडक़ों और हाइवे पर निराश्रित गौ वंश को पकड़ने के लिए करीब ढाई महीने पहले बनी गौ पेट्रोलिंग योजना अपनी शुरूआत में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। विभागों की बेरूखी और उनमें आपसी तालमेल की कमी के चलते योजना मूर्त रूप नहीं ले पाई है। आलम यह है कि योजना को आगे चलाने के लिए पशु संचालनालय ने हाथ खड़े कर दिए हैं। योजना तीस सितम्बर तक थी इसके बाद इसकी समीक्षा की जानी थी पर योजना को आगे बढ़ाने के बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है। भोपाल समेत प्रदेश के 6 जिलों में राजमार्गों को कैटल फ्री करने के लिए एक जुलाई से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इन छह जिलों के नौ राजमार्गों पर एक जुलाई से 31 अगस्त तक 3 हजार 953 निराश्रित गौवंश को सडक़ों से उठाकर गौशालाओं में शिफ्ट किया गया। इस अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 162 गौवंश की मौत हो गई और 510 गायें घायल हो गईं, जिनका चलित पशु चिकित्सा इकाई या स्थानीय पशु चिकित्सालय अमले के द्वारा उपचार किया गया।

ढाई महीने में ही टूटी गौ पेट्रोलिंग योजना की सांस

गौरतलब है कि सरकार ने बड़े जोश-खरोश के साथ योजना को शुरू किया था। लेकिन अब यह योजना पटरी से उतरने लगी है। इसका प्रमुख कारण विभाग के आला अधिकारियों का इसमें रूचि न लेना था। न तो लोक निर्माण विभाग ने इसमें रूचि ली और न ही नगरीय विकास विभाग ने अपेक्षित सहयोग किया। लिहाजा योजना पूरी तरह पशु संचालनालय विभाग पर निर्भर होकर रह गई। पायलट प्रोजेक्ट बनाते समय तय किया गया था कि योजना को अभी तीस सितम्बर तक चलाया जाएगा। इसके बाद पूरी योजना की समीक्षा की जाएगी। यह तिथि भी सोमवार को खत्म हो गई। जानकारी के मुताबिक अब तक योजना को लेकर कोई समीक्षा बैठक आयोजित नहीं की गई। वहीं पशु संचालनालय विभाग ने इस योजना को चलाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि उसके विभाग का काम मुख्य रूप से पशुओं का इलाज करना है। उसके पास इस योजना के लिए न तो पर्याप्त साधन है और न ही संसाधन और प्रशिक्षित अमला। विभाग कर्मचारियों की कमी से भी जूझ रहा है। विभाग की ओर से लिखे पत्र में यह भी कहा गया है कि योजना में लोक निर्माण विभाग और नगरीय विकास विभाग से भी सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। अपनी चिन्ता तों के बताने के साथ विभाग ने आगे योजना चलाने के लिए मार्गदर्शन भी मांगा है। योजना अब आगे चलेगी, इसे लेकर अब संशय की स्थिति बन गई है।

जुलाई में शुरू हुई थी योजना

बारिश के मौसम में शहर और प्रदेश की सडक़ों पर बड़े पैमाने पर जमा हो रहे गौ वंश के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने और बड़े वाहनों की चपेट में आकर मरने वाले गौ वंश को सुरक्षित रूप से प्रदेश की गौ शालाओं में भेजने के लिए जुलाई माह के पहले सप्ताह से गौ पैट्रोलिंग योजना तैयार की गई थी। इस योजना में तय किया गया था कि पशु संचालनालय विभाग सडक़ों पर पेट्रोलिंग कर सडक़ों और आसपास के हाइवे से गौवंश को हटाकर उन्हें सुरक्षित रूप से गौशाला भेजगा। योजना से लोक निर्माण विभाग और नगरीय विकास विभाग को भी जोड़ा गया था। इन विभागों को भी अपने स्तर पर इस योजना को अमली जामा पहनाने में सहयोग करना था। इसके लिए पशु संचालनालय विभाग को दो वाहन भी उपलब्ध कराए गए थे। योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भोपाल से शुरू किया गया था। भोपाल के परिणामों को देखकर इसे दूसरे शहरों में भी लागू किया जाना था। पहले महीने तो योजना ठीक-ठाक चली और सडक़ों से करीब सात सौ गौ वंश को पकडक़र आसपास की गौ शालाओं में भेजा गया पर इसके बाद योजना धीरे- धीरे मंद होती चली गई।

खाद्य मंत्री राजपूत ने केन्द्र सरकार के निर्णय पर आभार व्यक्त किया

फोर्टिफाइड चावल का निःशुल्क वितरण दिसम्बर-2028 तक जारी रहेगा

भोपाल। जागत गांव हमार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने केन्द्र सरकार के दिसंबर-2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) सहित सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने के निर्णय की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि फोर्टिफाइड चावल वितरण का उद्देश्य एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है।

प्रदेश में 5 करोड़ 45 लाख हितग्राहियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण- मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निःशुल्क फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। आँगनवाड़ी केन्द्रों और मध्यान्ह भोजन के लिये भी फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रतिमाह लगभग 1.75 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। इससे लगभग 5 करोड़ 45 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

क्या है फोर्टिफाइड चावल

भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अनुसार सामान्य चावल में पोषक तत्व मिलाकर फोर्टिफाइड चावल तैयार किया जाता है। फोर्टिफाइड चावल में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-बी एवं जिंक सम्मिलित हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व लोगों की आहार जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मिलाए जाते हैं।

राज्य सरकार के प्रयासों और किसानों के परिश्रम से मिलेट्स के रकबे में अप्रत्याशित बढ़ोतरी

अब श्रीअन्न उत्पादन में भी प्रदेश मार रहा बाजी

भोपाल। जागत गांव हमार

मप्र ऐसा राज्य बन चुका है, जहां पर श्री अन्न उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रहा है। यही वजह है कि प्रदेश उन राज्यों में शीर्ष पर पहुंच गया है, जहां पर तेजी से श्री अन्न उत्पादन में वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार के प्रयासों और किसानों के परिश्रम से मिलेट्स के रकबे में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020-21 में जहां इसका रकबा 67 हजार हेक्टेयर था, वह वर्ष 2023-24 में बढक़र 1.35 लाख हेक्टेयर रिकॉर्ड किया गया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्री अन्न उगाने वाले किसानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त राष्ट्र संघ में की गई पहल से वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अभिनव पहल से श्रीअन्न के उत्पादन के क्षेत्र में देश और प्रदेश को नई दिशा मिली है। कृषि क्षेत्र में की गई पहल के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आभार माना है। उन्होंने कहा कि किसानों की परिश्रम से आज प्रदेश में श्रीअन्न का रकबा पिछले 3 साल में बढक़र दोगुना हो गया है। मध्यप्रदेश में श्रीअन्न (मिलेट) के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं।

मिलेट्स की खेती खरीफ ऋतु में

प्रदेश में मिलेट फसले जैसे कोदो कुटकी, ज्वार- बाजरा रागी आदि किसानों द्वारा उगई जाती है। इनमें कोदो -कुटकी की खेती मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों जैसे मडला डिंडौरी शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, छिन्दवाड़ा आदि जिलो में की जाती है। रागी की खेती प्रदेश में डिण्डोरी, मण्डला और जबलपुर में व्यापक तौर पर की जाती है। प्रदेश के खरगौन, खण्डवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, बैतूल,राजगढ़ और गुना जिले में ज्वार की खेती होती है। प्रदेश में बाजरे की खेती मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में होती है। मिलेट्स की खेती मुख्यतः खरीफ ऋतु में की जाती है।

श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना होगी लागू

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने श्री अन्न उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राती दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का फैसला किया है। मध्यप्रदेश में श्री अन्न के विस्तार के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही मप्र राज्य मिलेट्स मिशन संचालित है। प्रदेश में श्री अन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फॉर्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के बाग से मिलेट फेडरेशन का पंजीयन कराया गया है। प्रदेश में वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में व्यापक तौर पर मनाया गया। मिलेट्स के उत्पादन और उपयोग के प्रोत्साहन के लिये कार्य म किए जा रहे है।

प्रोत्साहन के लिए मप्र राज्य मिलेट मिशन

मिलेट्स के प्रोत्साहन के लिये वर्ष 2023-24 में कप राज्य मिलेट मिशन की ओर से बीज वितरण, कृषक प्रशिक्षण, कृषक अध्ययन भ्रमण, सेमिनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर फूड फेस्टिवाल रोड-शो इत्यादि से मिलेट्स का प्रचार- प्रसर किया गया। इतना ही नहीं इंदौर में आयोजित एवं प्रवासी भारतीय दिवस एवं इन्वेस्टर्स समिट में श्री अन्न आधारित उत्पादों की ब्रांडिग की गई। भोपाल में हुए जी-20 (कृषि वर्किंग ग्रुप) सम्मेलन में श्री अन्न आधारित प्रदर्शनी लगाई गई थी। मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के सहयोग से निगम के समी होटल्स में मिलेट व्यंजन परोसे जा रहे हैं। सभी आउटलेट में मिलेट को ब्रॉण्डिग भी की जा रही है।

ठंड के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें

» डॉ. ब्रजेश सिंह
» डॉ. आनंद कुमार जैन
» डॉ. रणवीर सिंह
पशु औषधि विभाग
पशु चिकित्सा और पशु पालन महाविद्यालय, जबलपुर, मप्र

सर्दियों में हमारे यहाँ तापमान 5-60 से 220 तक होता है। इस तापमान में जहाँ पशुओं से अत्यधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है वहीं पशुओं को ठंडी हवाओं के प्रकोप से बचाना भी जरूरी है। इसीलिए सर्दियों में पशु आवास का विशेष महत्व होता है।

पशु घर में प्रत्येक गाय-भैंस के लिये कम से कम 5.5 फिट चैड़ी एवं 10 फिट लम्बी पक्की जगह होनी चाहिए। फर्श खुरदुरा होना चाहिये तथा नाली के लिये सही ढलान होना चाहिए। पशुशाला की दीवार 4-5 फिट ऊँची होनी चाहिये बाकी में जाली लगाये।

सर्दियों में रात के समय इस जाली वाले भाग में टाट या बोरी को सिलकर पर्दे लगायें, जिससे ठंडी हवाओं से पशुओं को बचाया जा सके। पशु घर की पश्चिमी दीवार पर 2 फिट चैड़ा और 1.5 फिट गहरा नाद बनाना चाहिये। नाद का आधार भूमितल से 1 फिट ऊपर होना चाहिये। नाद के साथ स्वच्छ जल की भी व्यवस्था होनी चाहिये। पानी का नाद सप्ताह में दो दिन चूने से पोत दें इससे पशुओं में कैल्सियम की कमी नही होगी तथा पशुओं में होने वाले विभिन्न संक्रमणों से भी बचाव हो सकता है। सर्दियों में जरूरी है कि पशुओं खासकर नवजात बछड़ें एवं बछियों को सर्दी से बचाने के लिये फर्श पर पुवाल का बिछावन डाले। इसकों समय-समय पर बदल दें जिससे इसमें नमी न आ जाये।

सर्दियों में पशु पोषण कैसे करें: एक वयस्क पशु को प्रतिदिन औसतन 6 किलो सूखा चारा और 15-20 किलों तक हरा चारा खिलाना चाहिये। फलीदार और बिना फ्लीदार हरे चारे को समान अनुपात में मिलाकर खिलाना चाहिये। हरे चारे की फसल को जब आधी फसल में फूल आ जाये तब काटकर खिलाना उपयुक्त रहता है। चारे को काटकर खिलाना लाभदायक होता है। सूखा चारा, हरा चारा, पशु आहार एवं खनिज मिश्रण मिलाकर सानी बनाकर प्रतिदिन 3-4 बार में देना चाहिये। इससे चारे की बर्बादी कम होती है और चारा सुपाच्य भी हो जाता है।

उपलब्ध चारे अथवा भूसे का अभाव कल के लिये संरक्षण कैसे करें: इस मौसम में 50-60 दिनों बाद बरसीम आना शुरू हो जाएगी। इस मौसम में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है पर गर्मियों के मौसम में चारा उपलब्ध नही हो पाता इसलिए जरूरी है कि अभाव काल के लिये चारे का संरक्षण किया जाये जो कि 'हे' बनाकर किया जा सकता है। 'हे' मुलायम तने वाली घासों से बनाई जाती है इसके लिये फसल को काटकर 5-10 किलो के बंडल बनाते हैं। इन बंडलों को एक दूसरे के सहारे से खड़ा करके धूप में सुखायें। सूखने की प्रक्रिया में जगह बदलते रहें तकि बंडल ठीक से सूख जायें।

भूसे को भी यूरिया से उपचारित करके उसमें प्रोटीन की मात्रा बढाकर उसे ज्यादा पौष्टिक बनाया जा सकता है। इसके लिये 4 किलो यूरिया को 40 लीटर पानी में घोलें। यह मात्रा 100 किलो भूसे के लिये पर्याप्त होती है। 100 किलो भूसे को पक्के फर्श या कच्चे फर्श में प्लास्टिक की शीट के ऊपर इस तरह फैलायें कि पर्त की मोटाई लगभग 3-4 इंच रहे। इसके ऊपर यूरिया

का घोल छिड़के फिर भूसे को पैरों से चल-चल कर या कूद-कूद कर दबायें। पुन: 100 किलो की भूसे की पर्त बनाये और यूरिया का घोल छिड़कें। इस तरह से 100-100 किलो की दस पतज़ बनायें एवं घोल का छिड़काव करने के बाद पैरों से दबाते जाए।

इस उपचारित भूसे को अब प्लास्टिक शीट से ढक दें और जमीन से छूने वाले किनारों पर मिट्टी अथवा पुवाल डाल दें एवं गोबर से लीप दें। इस तरह उपचारित भूसे के ढेर को गमीज़ में 21 दिन व सर्दी में 28 दिन के बाद खोलें।

पशुओं को खिलाने से पहले भूसे को लगभगग 10 मिनट तक खुली हवा में फैला दें जिससे उसकी गैस निकल जाए। शुरूआत में पशु को उपचारित भूस थोड़ा-थोड़ा दे बाद में आदत पड़ने पर पशु बड़े चाव से भूसा खाने लगता है।

इस मौसम में पशुओं में कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती है: सर्दियों में पशुओं में विभिनन प्रकार के रोगों के होने की सम्भावना रहती है जिसमें प्रमुख है- पशुओं में सर्दी जुखाम के लक्षण, निमोनिया जो कि सर्दी लगने अथवा पशुशाला में अत्यधिक नमी के कारण पनपे जीवाणुओ द्वारा होता है। आने वाली रबी की फसल के समय यदि पशु अत्यधिक हरा चारा मुख्यत: बरसीम खा ले या कि उसके आहार में कोई आकस्मिक बदलाव हो तो अफरा/पेट फूलने/ठसवंज की समस्या हो सकती है। इस मौसम में नवजात बछड़ों या बछिया में जीवाणु या विषाणुओं द्वारा होने वाला दस्त भी प्रमुख रूप से पाया जाता है।

पशुओं का इन रोगों से बचाव कैसे करें -

दस्त से नवजात के बचाव के लिये पशुशाला में साफसफाई का विशेष ध्यान रखें।

जन्म से लेकर दो माह तक गोवंशों को अलग सूखे, स्वच्छ एवं पूर्ण हवादार स्थान पर रखें। समय समय पर निर्जमीकरण करें।

गोवंशों के रहने की जगह पर फर्श पर सर्दियों में पुवाल बिछायें तथा समय-समय पर इसको बदलते रहें।

ठंडी हवा के थपेड़ों से बचाने के लिये इनमे टाट/बोरे के पर्दों का इस्तेमाल करें। दिन के समय पर्दे हटा दें ताकि धूप आ सके।

गोवंशों को जन्म के)घंटे के अन्दर खीस अवश्य पिलायें इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमत बढती है।

नवजात बछड़े/बछिया को शरीर के बजन के हिसाब से दूध पिलायें।

दस्त से बचाव के लिये दूध को गरम करने के बाद ठंडा करके पिलायें।

क्रीमियों के द्वारा होने वाले रोगों से बचाव के लिये समय-समय पर पशु चिकित्सक की सलाह पर क्रीमिनाशक दवापान करायें।

अफरा रोग से बचाव के लिये हरा चारा अत्यधिक मात्रा में न दें तथा पशु आहार में आकस्मिक बदलाव न करें।

पशुओं को सर्दी के मौसम में दाने के साथ सरसों का तेल मिलाकर खिलायें इससे उन्हें उर्जा मिलेगी, उनका पाचन सही रहेगा ।

सर्दियों में खुरपका, मुँहपका रोग होने की सम्भावना रहती है इससे बचाव के लिये टीकारण अक्टूबर महीने तक हो जाना चाहिये। पर यदि टीकाकरण न हुआ हो तो अतिशीघ्र टीकाकरण करायें। वाह्य परजीवी जैसे कि किलनी, जूँ इत्यादि से पशुओं का बचाव करें। इसके लिये पशुचिकित्सक से परामर्श प्राप्त कर दवा का इस्तेमाल करें। पशुओं में दिन में एक बार सख्त ब्रस से खुरैरा करें इससे वाह्य परजीवियों से बचाव होगा साथ ही साथ शरीर में रक्त का प्रवाह भी बढेगा और उनके उत्पादन में भी सुधार आएगा।

कॉकटेल पक्षियों की देखभाल और प्रबंधन

» डॉ. शिवम सिंह मेहरोत्रा
» डॉ. अनिल धाकड़
» डॉ. प्रवीण डोडव
» डॉ. आकाश सुमन
पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू मध्य प्रदेश

कॉकटेल पक्षी, जिसे आमतौर पर वीरो कहा जाता है, एक सुंदर और चंचल पालतू पक्षी है। इनकी खासियत इनकी रंगीनता और सामाजिक स्वभाव है। यदि आप कॉकटेल को पालतू बनाना चाहते हैं, तो उनकी देखभाल और प्रबंधन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। कॉकटेल के लिए एक उपयुक्त आवास सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। उन्हें एक बड़े और खुली जगह वाले पिंजरे की आवश्यकता होती है। पिंजरे का आकार कम से कम 24×24×36 होना चाहिए। इसके अलावा, पिंजरे के अंदर झूलने वाले झूले, चोखे और छिपने के स्थान जैसे तत्व शामिल करें।

काकटेल पक्षियों के आवास का प्रबंधन ऐसा होना चाहिए, जहां पर सूरज की रोशनी पहुंच सके, लेकिन अत्यधिक गर्मी या ठंड से दूर हो। उन्हें एक बड़े और खुली जगह वाले पिंजरे की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, पिंजरे के अंदर झूलने वाले झूले, चोखे और छिपने के स्थान जैसे तत्व शामिल करें।

सफाई: पिंजरे की नियमित सफाई भी आवश्यक है। पिंजरे के फर्श, फीडर और पानी के बर्तन को रोजाना धोएं। हर हफ्ते पिंजरे की गंदगी को साफ करें और पिंजरे के अंदर की सभी वस्तुओं को कीटाणुरहित करें। यह न केवल आपके कॉकटेल को स्वस्थ रखेगा, बल्कि उनकी खुशी और गतिविधियों में भी वृद्धि करेगा।

पोषण: कॉकटेल पक्षियों के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। उन्हें विभिन्न प्रकार के बीजों, फल, सब्जियां और विशेष रूप से तैयार किए गए कॉकटेल फूड की आवश्यकता होती है। बीजों के मिश्रण को खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हों।

फल और सब्जियाँ: काकटेल पक्षियों के फलों और सब्जियों का समावेश भी आहार में करें। गाजर, सेब, पपीता और हरी पत्तेदार सब्जियाँ कॉकटेल के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इन्हें ताजगी से रोजाना दें। ध्यान रखें कि कुछ फल ऐसे भी होते हैं, जो काकटेल पक्षियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जैसे कि एवोकाडो इसलिए इन्हें न दें।

सामाजिक व्यवहार: कॉकटेल पक्षी बेहद सामाजिक होते हैं और इन्हें अकेले रखना उन्हें तनाव में डाल सकता है। यदि संभव हो, तो इन्हें दूसरे कॉकटेल या अन्य पालतू पक्षियों के साथ रखें। नियमित रूप से इन्हें बाहर निकालें ताकि वे आपके साथ समय बिता सकें। कॉकटेल के साथ बातचीत करें और उन्हें अपने हाथों पर बैठने की आदत डालें। इससे उनका सामाजिक व्यवहार बेहतर होगा।

स्वास्थ्य देखभाल: कॉकटेल पक्षियों का स्वास्थ्य उनकी देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्हें हर साल एक पशु चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। यदि आपको आपके पक्षी में कोई असामान्य लक्षण दिखे, जैसे कि खाना न खाना, वजन कम होना या पंखों का गिरना, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

टीकाकरण: कॉकटेल के लिए आवश्यक टीके भी हो सकते हैं। अपने पशु चिकित्सक से सलाह लें कि कौन से टीके आपके पक्षी के लिए जरूरी हैं। कॉकटेल पक्षियों की देखभाल एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह एक बहुत संतोषजनक अनुभव भी है।

यदि आप उनकी उचित देखभाल करते हैं, तो ये न केवल लंबे समय तक जीवित रहेंगे, बल्कि आपको खुशी और स्नेह भी देंगे। इनकी चंचलता और प्यार भरा व्यवहार आपके घर में खुशी का माहौल बनाएगा। इसलिए, कॉकटेल को अपनाने से पहले उनकी देखभाल के सभी पहलुओं को समझें और एक खुशहाल पालतू अनुभव का आनंद लें।

पांच सालों में एक तिहाई घट गई भूमि जोत किसान परिवारों पर कर्ज का बकाया भी बढ़ा

एक ओर जहां किसानों की मासिक घरेलू आय बढ़ रही है, वहीं उन पर व्यय और कजज का बोझ भी बढ़ रहा है। बढ़ी हुई कमाई के साथ किसान परिवार गैर खाद्य खर्चों की तरफबढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा चिंताजनक यह है कि उनके पास खेती के लिए मौजूद भूमि जोत भी सिकुड़ती जा रही है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ताजा सर्वे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस) 2021-22 आंकड़ों में यह बात सामने आई है। यह नाबार्ड का 2016-17 के बाद किया गया दूसरा सर्वेक्षण है। नाबार्ड का यह सर्वे कोविड-19 के बाद की अवधि के लिए कई आर्थिक और वित्तीय संकेतकों पर 1 लाख ग्रामीण परिवारों से संबंधित प्राथमिक सर्वेक्षण-आधारित जानकारी देता है। सर्वेक्षण के मुताबिक देश में किसानों के पास 2016-17 में जहां औसत खेती के लिए भूमि जोत 1.08 हेक्टेयर थी वहीं, यह 2021-22 में घटकर 0.74 हेक्टेयर ही रह गई है। यानी करीब एक तिहाई (31 फीसदी) की कमी आई है। ताजा सर्वेक्षण में किसानों के लिए एक उत्साहजनक खबर भी मौजूद है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2016-17 में किसानों की औसत मासिक घरेलू आय जहां 8,059 रुपए थी, वहीं अब 2021-22 में यह 57.6 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर 12,698 रुपए तक हो गई है। हालांकि ग्रामीण आय की 9.5 फीसदी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) की वृद्धि सुखद है, लेकिन औसत मासिक व्यय में वृद्धि भी दर्ज की की है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2016-17 में ग्रामीण परिवार जहां महीने में 6,646 औसतन खचज कर रहे थे वहीं यह अब बढ़कर 11,262 रुपए हो गया है। यानी 2016-17 के बाद मासिक खर्च में 69.4 फीसदी का इजाफा हुआ है।

इसका साधारण अर्थ है कि लोग ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन साथ ही वे ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं। इस व्यय में भोजन के लिए खर्च का हिस्सा 51 से घटकर 47 फीसदी हो गया है, जो यह बताता है कि ग्रामीण परिवार गैर-खाद्य खर्चों की ओर बढ़ रहे हैं। इससे खर्च करने की प्रवृत्ति और खाद्य सुरक्षा पर भी सवाल उठता है। आय और व्यय के इस गणित के अलावा किसान परिवारों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सर्वेक्षण के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण लेने वाले परिवारों की संख्या 47.4 प्रतिशत से बढ़कर 52 प्रतिशत हो गई है, जो वित्तीय दबाव का संकेत है। इसका अर्थ हुआ कि 2016-17 में यदि हर 100 घरों में से लगभग 47 (47.4प्रतिशत) पर किसी न किसी तरह का कर्ज था, यानी उन पर पैसे बकाया थे तो 2021-22 तक यह संख्या बढ़कर हर 100 घरों में से 52 (52.0 फीसदी) हो गई।

करीब 200 प्रकार के औषधीय पेड़, पौधे और झाड़ लगे हैं, कई बार मिल चुका है पुरस्कार

कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता नहीं मिली तो शुरू की औषधीय पौधों की खेती

औषधीय खेती से लखन ने कायम की मिसाल, अब विदेशी भी आते हैं देखने

बमोरी (विदिशा)। जागत गांव हमार

जिले के नटेरन जनपद क्षेत्र के किसान लखन पाठक 12 साल से औषधीय खेती कर रहे हैं। उन्होंने परंपरागत खेती छोड़ कर इसको अपनाया और अब 13 बीघा में औषधीय खेती कर रहे हैं। किसान लखन पाठक का कहना है कि पहले साल खेती में जब मुनाफा नहीं हुआ तो लगा कि बर्बाद हो जाऊंगा। अपनी गलतियों से सीखा और धैर्य के साथ मेहनत की। इसका परिणाम है कि अब सालाना 14 लाख रुपए की बचत हो रही है। फार्म पर करीब 200 प्रकार के औषधीय पेड़, पौधे और झाड़ लगे हैं। यहां केवकंद, चित्रक, सर्पगंधा, अश्वगंधा, हठजोड़, आमा हल्दी सहित करीब 50 प्रजाति की औषधि वे हर साल लगाते हैं। उनकी प्रोसेस कर औषधियों का पाउडर, बीज, छाल और जड़ को लोगों तक पहुंचाते हैं।

सरकारी नौकरी के लिए किया प्रयास, लेकिन नहीं मिली सफलता, शुरू की खेती- 48 साल के किसान लखन पाठक ने 1997 में बायोलॉजी से बीएससी कम्प्लीट की। इसके बाद शिक्षक सहित अन्य सरकारी नौकरी में किस्मत आजमाई, लेकिन दो साल प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद घर में पिताजी के साथ 55 बीघा खेत में सोयाबीन, गेहूं, चना, मक्का सहित अन्य पारंपरिक फसल उगाई। इसमें सालाना दो लाख रुपए तक की बचत हो जाती थी। तब रेट और खर्च भी कम थे।

आय बढ़ाने कुछ नया करने की सोच-घर की जरूरत और खर्च बढ़ने पर खेती में कुछ नया करने का विचार आया, ताकि आय बढ़े। इसके लिए मैं खेती में प्रयोग करता रहता था। मेरे मामा का बेटा नीमच के एक किसान परिवार से मिला। वे अश्वगंधा की खेती करते थे। मामा के बेटे ने मेरी मोबाइल पर बात कराई। मैंने अश्वगंधा की खेती के बारे में जाना। उसी सप्ताह मैं नीमच पहुंचा। वहां दो दिन रहकर आश्वगंधा लगाने की ट्रेनिंग ली। उनसे 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 35 किलो बीज लाया।

हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का सर्टिफिकेट लिया

औषधि उगाने के बाद मप्र के आयुष विभाग से अनुमति लेकर पाली में घर पर ही औषधि केंद्र खोला है। ऑनलाइन पढ़ाई कर केरल के तिरुवनंतपुरम से ट्रेडिशनल कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। खेत से प्राप्त औषधियों से वे क्षेत्र के लोगों का इलाज करते हैं। लखन का कहना है कि यहां लगी औषधि अलग-अलग प्रकार से उपयोग होती है। कुछ का तेल निकालकर और कुछ को कूटकर दवा बनाते हैं। ज्यादातर पाउडर के रूप में इस्तेमाल की जाती है।

नीमच मंडी में बेचते हैं उपज

प्रदेश के नीमच में औषधियों की मंडी लगती है। वहां उपज के अच्छे दाम मिलते हैं। अश्वगंधा, अकरकरा, केवकंद सहित अन्य औषधि को वे नीमच ले जाकर बेचते हैं। वहां भाव के साथ खरीददार भी ज्यादा मिलते हैं। हेल्थ केयर का सर्टिफिकेट लेने के बाद घर ही आयुर्वेद चिकित्सालय खोल लिया है। अपने खेत में उगी जड़ी-बूटियों से लोगों का इलाज भी करते हैं। ऐसे में उपज मंडी की अपेक्षा चार से पांच गुना महंगी बिकती है।

खेती देखने विदेश से आए लोग

लखन ने बताया कि वे जब भी किसी औषधि का नाम सुनते हैं तो उसके बारे में जानकारी जुटाने लगते हैं। इसके लिए

ऑनलाइन और विदिशा, भोपाल के आयुर्वेद के जानकार की मदद लेते हैं। छह साल पहले एक एनजीओ के अफसर हमारे क्षेत्र के भ्रमण पर आए थे। वे मेरा खेत देखकर गए थे। उसके बाद मैं उनसे जुड़ा। वहां के लोगों से औषधीय खेती के बारे में जाना। एनजीओ के माध्यम से नीदरलैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक व किसान प्राकृतिक औषधि की खेती देखने आ चुके हैं।

कई बार मिल चुका है लखन को पुरस्कार

पहले तीन साल अश्वगंधा पर फोकस किया। इसके बाद अकरकरा, केवकंद के साथ औषधीय पौधे लगाए। चरक संहिता सहित अन्य पुस्तकें पढ़ने के बाद करीब 200 प्रकार के पेड़-पौधे लगाए। यहां उपज को प्रोसेस करने के लिए आयुष विभाग से दवाओं की पैकिंग की अनुमति ली। उपज की छाल, तेल निकालने से लेकर उसका चूर्ण बनाने के लिए छह लाख रुपए से मशीनें लगवाई हैं। विदिशा जिले के लखन को कई बार पुरस्कार मिल चुके हैं।

इंदौर में पढ़ाई कर रहा बेटा

परिवार में पत्नी व तीन बच्चों के अलावा दो भाई और माता-पिता हैं। बड़ा बेटा इंदौर से बीबीए कर रहा है। बिटिया 10वीं और बेटा 11वीं में है। दोनों शमशाबाद में पढ़ाई कर रहे हैं। बड़े भाई शमशाबाद में स्कूल चलाते हैं। छोटा भाई भोपाल में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है। आउटलेट चलाने से लेकर खेतों की देखरेख में पत्नी बराबर सहयोग करती है।

ब्राह्मी- कड़बी प्रजाति लगाते हैं। यह स्मरण शक्ति बढ़ाने में उपयोग करते हैं। इसके साथ ही कालमेघ, बाह्मी और नाय कड़बी होती हैं। यह डायबिटीज, पुराना बुखार सहित अन्य रोग को दूर करने में उपयोग करते हैं।

चित्रक- इससे चित्रकादि बटी बनती है। यह पेट संबंधी रोग में काम आती है। स्किन डिजीज खास तौर पर सफेद दाग आदि में इसका उपयोग करते हैं।

सर्पगंधा- यह हाई ब्लडप्रेशर, कॉलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। इसकी जड़ का उपयोग करते हैं। 18 महीने पुरानी जड़ का पाउडर बनाकर उसमें अश्वगंधा, अर्जुन सहित अन्य जड़ी मिलाकर देते हैं।

घोड़ा बच- बच्चों का हकलाना दूर करती है।

एलोवेरा- स्किन, बाल और पेट संबंधी बीमारियों को दूर करता है।

लेमन ग्रास- थाइरॉइड के लिए।

हठजोड़- हड्डी जोड़ने के लिए।

पुर्ननबा- पथरी, लिवर और किडनी रोग के लिए।

बकायन - पाइल्स के लिए कारगर है।

अर्जुन - हृदय रोग के लिए होता है।

मैदा लकड़ी - इत्र आदि बनाने में छाल का उपयोग होता है। इसके साथ ही शीकाकाई, रीठा, आंवला, हरड़, मुनगा सहित 30 प्रजाति के औषधीय पेड़ लगे हैं।

पहली बार में नहीं हुआ मुनाफा

लखन पाठक ने बताया कि 2012 में पांच बीघा में अश्वगंधा की खेती की। पहले साल में पारंपरिक खेती के बराबर ही आय रही। हालांकि मेहनत उससे ज्यादा लगी। एक बार तो लगा कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, फिर विचार आया कि जब खेती ही करना है तो एक बार और मेहनत करते हैं। इसमें परिवार का संबल मिला। पहली बार में मैंने जो गलतियां की थी, उनसे सीखा। उनमें सुधार किया। 2013-2014 में भाइयों को राजी कर 23 बीघा में अश्वगंधा लगाया। इस बार सही समय पर सितंबर के अंत में फसल बोई। इस बार बीज घर का ही था। मौसम ने भी साथ दिया। 23 बीघा में करीब आठ लाख रुपए की बचत हुई। यह हमारी खेती की अब तक की सर्वाधिक आय थी। अगले साल इसका क्षेत्र बढ़ाना था। तीनों भाइयों ने सहमति से खेत का बंटवारा कर लिया। इसके बाद मैं करीब 13 बीघा में औषधीय खेती कर रहा हूं। सामान को प्रोसेस कर विदिशा और गांव में अपनी दुकान से लोगों को उपलब्ध कराता हूं। इसके लिए आयुष विभाग से अनुमति ले रखी है।

टिश्यू कल्चर तकनीक का लिया सहारा, प्राकृतिक खेती से मिलने वाली उपज की भारी मांग

केले-सब्जियों की खेती से 10 लाख कमा रहे छिंदवाड़ा के पूरनलाल

छिंदवाड़ा। जागत गांव हमार

प्राकृतिक खेती के फायदों और उससे होने वाली कमाई को जानने के बाद पूरनलाल ने केले की खेती शुरू की। इसके लिए उन्होंने टिश्यू कल्चर से तैयार जी-9 केले को अपने खेतों में लगाया। पैदावार इतनी अच्छी रही कि दूर-दूर तक उनका नाम हो गया। इतना ही नहीं, एक एकड़ में की गई केले की खेती से पूरनलाल ने 4 लाख रुपये की कमाई कर ली है। पूरनलाल की ये पूरी कमाई प्राकृतिक खेती से मिल रही है।

नए दौर में खेती भी अब नए तरीके से हो रही है। परंपरागत खेती को छोड़कर लोग प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं और अच्छी कमाई पा रहे हैं। प्राकृतिक खेती को लोग उन्नत खेती का जरिया बनाकर अपनी कमाई बढ़ा रहे हैं। कमाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्राकृतिक खेती से मिलने वाली उपज की भारी मांग है। सेहत के लिहाज से प्राकृतिक खेती लाभदायक है, इसलिए बाजारों में इसकी मांग में तेजी है। ऑनलाइन मार्केट में भी ऐसे उत्पाद की भारी मांग है। ऐसे ही एक किसान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के भुमका गांव के हैं जिन्होंने प्राकृतिक तरीके से केले की खेती शुरू की और अब अच्छी कमाई ले रहे हैं। इनका नाम है पूरनलाल। प्राकृतिक खेती के फायदों और उससे होने वाली कमाई को जानने के बाद पूरनलाल ने केले की खेती शुरू की। इसके लिए उन्होंने टिश्यू कल्चर से तैयार जी-9 केले को अपने खेतों में लगाया। पैदावार इतनी अच्छी रही कि दूर-दूर तक उनका नाम हो गया। इतना ही नहीं, एक एकड़ में की गई केले की खेती से पूरनलाल ने 4 लाख रुपये की कमाई कर ली है। पूरनलाल की ये पूरी कमाई प्राकृतिक खेती से मिल रही है।

सब्जी-केले से 10 लाख की कमाई

आज पूरनलाल किसान से केला व्यापारी बन गए हैं क्योंकि वे खेत में उगाए केले का बड़ा व्यापार करने लगे हैं। किसान पूरनलाल प्राकृतिक पद्धति से केले की खेती के अलावा बैंगन, टमाटर, मक्का की फसल भी उगा रहे हैं। वहीं उन्होंने अपने खेत में आम, कटहल, आंवला, सेब, एप्पल बेर, ड्रेगन फ्रूट, नीबू, संतरा और काजू के पौधे भी लगाए हैं। पूरनलाल ने अपने खेत में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम (टपक सिंचाई पद्धति) लगा रखा है। वह अपनी फसल के अवशेषों का सही ढंग से निपटान कर इससे खाद भी पैदा कर रहे हैं। यही खाद इनकी फसल के लिए अमृत का काम कर रही है। इससे उनके खेत की मिट्टी की क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है। साथ ही मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ रही है।

केले की खेती के अलावा कड़कनाथ मुर्गा पालन, बकरी पालन भी

पूरनलाल बताते हैं कि उनके खेत का केला जबलपुर मंडी में छिंदवाड़ा का केला के नाम से बिकता है। जहां आम केला 15 से 18 रुपये किलो बिकता है, वहीं पूरनलाल के खेत का केला 25 रुपये किलो तक बिकता है। इससे पूरनलाल की कमाई बढ़ रही है। किसान पूरनलाल केले की खेती के अलावा कड़कनाथ मुर्गा पालन, बकरी पालन का काम करते हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त कमाई हो रही है। पूरनलाल के पास कुल 6 एकड़ जमीन है जिस पर वे प्राकृतिक तरीके से फलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं। आज पूरनलाल सालाना 10 लाख रुपये की कमाई कर रहे हैं।

कोदो, कुटकी और सांवा को बढ़ावा देने सिंगरौली में मप्र की दूसरी बड़ी प्रसंस्करण इकाई का लोकार्पण

सिंगरौली। जागत गांव हमार

कोदो, कुटकी और सांवा को बढ़ावा देने सिंगदेव महिला किसान उत्पादक प्रोड्यूसर कम्पनी लि की प्रसंस्करण इकाई का लोकार्पण ग्राम जरहा में शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा वर्चुअल के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री राज्यमंत्री राधा सिंह थी। अध्यक्षता देवसर के विधायक राजेन्द्र मेश्राम ने की। इस मौके पर सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला, जिला पंचायत के मुख्य कायज़्पालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह नागेश सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

राज्य मंत्री राधा सिंह ने कहाकि प्रदेश सरकार अन्न मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाए संचालित कर रही है। पहले यह अनाज जन जाति बाहुल्य जिले में मोटे अनाज परम्परागत रूप से उत्पादित होते रहे, किंतु आज इस अनाज के लिए बड़े शहरों, बाज़ारों में मांग की जा रही है। इस प्लांट का शुभारंभ होने से रोजगार के अवसर मिलेंगे । आपने महिला स्व सहायता समूह की बहनों से बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।

देवसर के विधायक मेश्राम ने कहा कि कोदो -कुटकी एक जिला एक उत्पाद के तहत सिंगरौली जिले में चिन्हित है। मैंने ही सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा में प्लांट स्थापित करने की मांग की थी। जो आज मूर्तरूप ले रही है। प्रदेश के दूसरे बड़े प्रसंस्करण प्लांट के खुलने पर खुशी होकर उन्होंने देवसर विधानसभा के सभी समूह की बहनों को दीपावली त्योहार के लिए दो दो हजार रूपये देने की घोषणा की। सिंगरौली के विधायक शाह ने कहा कि गेहूं -चावल या दूसरे अनाज जो उत्पादित हो रहे हैं वे खाद डालने से इनके रासायनिक तत्वों के कारण बीमारियां होने की संभावना रहती है । इनसे बचने के लिए मोटे अनाज कोदो कुटकी की बड़ी मांग है। इस प्लांट के माध्यम से प्रदेश स्तर तक एक अच्छी मार्केटिंग होगी। सभी बहनों को अच्छे रोजगार के साथ -साथ फायदे होंगे।

समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रहीं हैं महिलाएं

कलेक्टर शुक्ला ने कहा कि सिंगरौली जिले में महिला स्व सहायता समूह का एक अच्छा गठन हुआ है। समूहों के माध्यम से महिलाएं आत्म निर्भर हो रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित इस प्लांट का उद्देश्य मोटे अनाजों को बढ़ावा देकर किसानों की आय को बढ़ाना है और जिले में रोजगार उपलब्ध कराना है । कोदो कुटकी एवं सांवा की खरीदी करना है। कार्यक्रम के दौरान स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कायज़्पालन अधिकारी अनुराग मोदी, सीईओ जनपद बैढ़न अनिल तिवारी, लेखा अधिकारी रक्षा सिंह, डीपीएम मंगलेश्वर सिंह, सरपंच रामकरण वर्मा , पूर्व सरपंच रामकृपाल शाह, प्रोड्यूसर कम्पनी के राज कुमार, सौरभ, सर्वेश, अमित कुमार, आजीविका मिशन की दीदी सुषमा जायसवाल, सत्यवती ,सुमित्रा सहित बड़ी संख्या में बहनें उपस्थित थीं।

नर्मदापुरम में किसान खेत पाठशाला का आयोजन

नरवाई प्रबंधन पर किसानों को मिली अहम जानकारी

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत बनवारी में किसान खेत पाठशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देशानुसार जिले के प्रत्येक गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर पिपरिया विकासखंड के एसडीएम, सरपंच रीना रघुवंशी, संसद प्रतिनिधि खूबचंद रघुवंशी और प्रगतिशील कृषक सुजीत रघुवंशी समेत अन्य अधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे। इस किसान खेत पाठशाला का मुख्य उद्देश्य किसानों को नरवाई प्रबंधन और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करना था। कृषि विभाग ने किसानों को मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में किसानों को नरवाई में आग न लगाने और डीएपी के वैकल्पिक उर्वरकों जैसे एनपीके, एसएसपी, टीएसपी के संतुलित उपयोग की सलाह दी गई। इसके अलावा,

उद्यानिकी विभाग ने फसल पौध योजना और पीएमएफएमई योजना की जानकारी दी। पाठशाला में किसानों को बेहतर खेती के लिए उपयोगी जानकारी देने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर कई प्रगतिशील कृषक और अन्य अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने किसानों के साथ अपने अनुभव साझा किए।

आम के संकलन पुस्तिका का दीक्षान्त समारोह में किया गया विमोचन

रीवा। कृषि महाविद्यालय रीवा के अखिल भारतीय समन्वित फल अनुसंधान परियोजना, फल अनुसंधान केंद्र रीवा के वैज्ञानिकों डॉ टीके सिंह, डॉ अखिलेश कुमार, सुधीर कुमार सिंह एवं डॉ एसके त्रिपाठी द्वारा लिखित पुस्तिका में आम की विभिन्न प्रजातियों का सचित्र वर्णन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से रीवा में लगाई जाने वाली आम की फसलें है, जिसका विमोचन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के 17 वे दीक्षान्त समारोह में किया गया। इस आम की संकलित पुस्तिका का विमोचन लखन सिंह पटेल, राज्य मंत्री, कुलपति डॉ प्रमोद कुमार मिश्रा, संकाय प्रमुख कृषि डॉ डीके खरे, संकाय प्रमुख उद्यान डॉ एसके पांडेय द्वारा किया गया। इस अवसर पर अधिष्ठाता रीवा डॉ एसके त्रिपाठी, डॉ टीके सिंह उपस्थित रहे। वैज्ञानिकों को कृषि महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा के समस्त स्टाफ ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

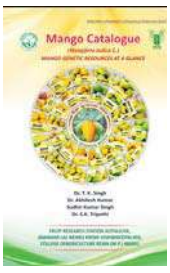

फिशरी कॉलेज में 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन

जबलपुर। आधारताल स्थित फिशरी कॉलेज में 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन गत दिवस हुआ। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉलेज के डीन डॉ. एसके महाजन ने कहा प्रशिक्षण कार्यक्रम से मत्स्य पालन के क्षेत्र में विस्तार एवं नवाचार को बल मिलेगा। साथ ही साथ समेकित कृषि पद्धति एवं मूल्य वर्धित उत्पाद बनाने की विधि से मत्स्य कृषक आर्थिक रूप से संबल बन सकेंगे। कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख रवि पाटिल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ट्रेनिंग में रतलाम व देवास के 25 मत्स्य उद्योग मंडल संचालक एवं प्रबंधकों सहित

प्रशिक्षणार्थियों को मत्स्य प्रक्षेत्र का प्रबंधन मत्स्य कृषि में नई तकनीकी तथा मूल्य वधिज़्त उत्पाद जैसे मछली के कटलेट, फिश फिंगर एवं फ्ऽिश चकली सहित मछली अचार बनाने की विधि को प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. माधुरी शर्मा एवं सह समन्वयक डॉ. प्रीती मिश्रा रहीं। समापन अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिवमोहन सिंह परियोजना प्रबंधक दीपक वर्मा, टीचिंग एसोसिएट अनिल केवट, सत्येंद्र कटारा, शिवानी पाठक, प्रियंका गौतम, प्रतीक कुमार तिवारी का सहयोग रहा।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 17 वां दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन

जो प्रतिज्ञा ली है उसका पालन जीवन अंत तक करना: राज्यपाल

अंजली चौरसिया, जबलपुर। जागत गांव हमार

जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि का 17 वां दीक्षांत समारोह मंगलवार की सुबह 10.40 पर दीक्षांत शोभायात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एदल सिंह कंसाना, मंत्री, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, विशिष्ट अतिथि डॉ. अनुपम मिश्रा, कुलपति, केन्द्रीय कृषि विवि, इम्फाल, कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा सहित प्रमंडल सदस्य मंचासीन रहे। विवि के कुलपति डॉ. मिश्रा द्वारा स्वागत उद्बोधन एवं विवि के प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलाधिपति मंगू भाई पटेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा आज आप कृषि के छात्र दीक्षित हुए हैं आप सारा जीवन जिज्ञासू बनकर जीयें तभी देश के कृषि के क्षेत्र में और तरक्की करेगा। पयाज्वरण और जैव विविधता को नुकसान न पहुंचे इस दिशा में शोध कायज करते हुए पोषक तत्वों से भरपूर नई किस्मों को किसानों तक पहुंचाना उद्देश्य होना चाहिए। आप छात्रों को यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा पानी पीयें, मिलेट्स से बना हुआ भोजन करें और नियमित योगाभ्यास करें और भरपूर नींद लें। उन्होंने कहा कि आज आपने जो प्रतिज्ञा ली है उसका पालन जीवन अंत तक करना।

ये अतिथि हुए समारोह में शामिल

कार्यक्रम में कुलाधिपति व अतिथियों द्वारा 38 छात्र-छात्राओं को गोल्ड मेडल व 15 छात्र-छात्राओं को नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही समारोह में वर्ष 2020-21, 2021-22 व वर्ष 2021-22 के पास आऊट 1821 स्नातक, 769 स्नातकोत्तर एवं 139 पीएचडी के विद्यार्थियों सहित 2729 छात्र-छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई। समारोह का समापन 12 बजे राष्ट्रगान के साथ हुआ। समारोह में विधायक अभिलाष पांडे, मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. डॉ. अशोक खंडेलवाल, आरडीयू कुलगुरु राजेश कुमार वर्मा, वीयू कुलपति डॉ. मनदीप शर्मा, कमिश्नर अभय वर्मा, आईजी अनिल कुशवाह, कलेक्टर दीपक सक्सेना, एसपी आदित्य प्रताप सिंह, सुलभ अंकित गौंटिया, संयुक्त संचालक कृषि केएस नेताम सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जलवायु समुत्थानुशील कृषि पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित

जलवायु समुत्थानुशील कृषि पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित

टीकमगढ़ ।जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के बारे में प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. एसके जाटव, डॉ. आई.डी. सिंह और जयपाल छिगारहा तथा बोरलॉग अंतराज्ञ्रीय संस्थान के तरफ से डॉ. पंकज कुमार, वैज्ञानिक, राजेश राय, दिवाकर सिंह, ने मिलकर किसानों को नई कृषि तकनीकियों के बारे में प्रशिक्षण दिया ।प्रशिक्षण के मुख्य अतिथि श्रीमान शिव मोहन गिरी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, एवं कोडिया, हसगोरा, चंदेरी खास एवं प ण्डेर के 45 किसान उपस्थित रहे ।

आगामी रबी में गेहूं की बुवाई की तकनीक पर विशेष रूप से जलवायु परिवतज्न के दौर में खेती को नई विधियों से करने पर किसानों को बताया गया । किसानों ने शून्य जुताई या बिना जुताई के बुवाई सीड ड्रिल से बुवाई कैसे करें पर प्रशिक्षण दिया तथा जो कुछ किसान पिछले साल इस तकनीक से बुवाई करके लाभान्वित हुए थे उनमें संजय सिंह बुंदेला, रतिराम सोर, ग्राम कोडिया एवं सुनील कुशवाहा ग्राम हसगोरा ने अपने अनुभवों को बताया कि बिना जुताई के सीधा शून्य जुताई मशीन से एक एकड़ में 40 किलोग्राम बीज का उपयोग करके 20 क्विंटल उपज एक एकड़ में प्राप्त किया साथ ही 2500-3000 रु जो खचाज़ खेत के तैयार करके बुवाई में लगता है जिससे बचत लागत में कमी आई ।

इस विधि में खेत में खरपतवार भी कम खचेज़ पर नियंत्रण होता है शून्य जुताई विधि से सीधे बुवाई करने पर जड़ों का विकास अच्छा होता है और फ्सल माचज़ अप्रैल में तेज हवा के साथ गिरने से बचती है । सामान्य बुवाई में किसानो द्वारा 15-20 किलो अधिक बीज का उपयोग किया जाता था वह भी बचत में आया । डॉ. प्रजापति का कहना था कि मिट्टी की भौतिक रासायनिक और जैविक दशाओं में सुधार होता है । शून्य जताई आने वाले भविष्य में खेती में अपने से हम उपज, पर्यावरण का संरक्षण आदि कर सकेंगे । डॉ. किरार ने किसानों को रवि में प्रदर्शन हेतु मिट्टी की जांच आवश्यक करने पर जोर दिया ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिव मोहन गिरी द्वारा किसान वैज्ञानिको द्वारा जलवायु अनुकूल तकनीक पर दी गई जानकारी पर भरोसा कार उसे प्रदर्शन में अपनाने और अपनी लगत कम कार उत्पादन बढ़ाये । बीसा संस्थान जबलपुर कि संस्था द्वारा बिना जुताई कार मशीन बुवाई कर प्रदर्शन तकनीक का लाभ उठायें।

डॉ. सुरेश इटापू बने सोया फूड एसोसिएशन के अध्यक्ष

भोपाल। जागत गांव हमार

सोया फूड प्रमोशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन (एसएफपीडब्ल्यूए) की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में डॉ. सुरेश इटापू को नए अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की घोषणा की गई। इस चुनाव का महत्व केवल एसोसिएशन के सदस्यों के लिए नहीं है, बल्कि यह भारतीय सोया उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है। डॉ. इटापू के नेतृत्व में, एसएफपीडब्ल्यूए ने नई रणनीतियों और पहलों के माध्यम से इस उद्योग को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिससे न केवल व्यवसायिक अवसर बढ़ेंगे बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। डॉ. इटापू ने जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर से खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मास्टर और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने अपने करियर के दौरान अमेरिका के पर्ड्यू विश्वविद्यालय में खाद्य विज्ञान विभाग में पांच साल तक कार्य किया। उनके पास खाद्य उद्योग में तकनीकी और प्रबंधन का व्यापक अनुभव है, जो उन्हें इस नई भूमिका में एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

उनकी विशेषज्ञता केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में सोया और खाद्य उद्योगों के साथ मिलकर कार्य किया है। उनका अनुभव उन्हें बाजार की मांग और उपभोक्ता व्यवहार को समझने में मदद करता है, जो उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में महत्वपूर्ण साबित होगा। भारत में सोया उद्योग ने पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। डॉ. इटापू ने कहा, भारत में सोया उद्योग ने एक आला बाजार से विकसित होकर कृषि परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। मुख्य रूप से शाकाहारी आबादी और किफायती प्रोटीन स्रोतों की बढ़ती मांग ने सोया उत्पादों की लोकप्रियता को बढ़ाया है। सोयाबीन प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो इसे उपभोक्ताओं के लिए एक आकषज़क विकल्प बनाता है।

मिथकों को दूर करने जैसे आवश्यक विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे

भारत सरकार ने सोयाबीन की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं, जिनमें बीज और उर्वरकों के लिए सब्सिडी शामिल हैं। इससे किसानों को अपनी उपज बढ़ाने और बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने में मदद मिली है, जो अंततः उद्योग की विकास दर को बढ़ा रहा है। डॉ. इटापू ने कई प्रमुख पहलों की योजना बनाई है, जिनमें उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए वेबिनार और सोया कॉन्क्लेव का आयोजन शामिल है। ये कार्यक्रम विपणन रणनीतियों, लागत प्रबंधन, गुणवत्ता सुधार, और सोया उत्पादों के बारे में मिथकों को दूर करने जैसे आवश्यक विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

किसानों की दी जाएगी योजनाओं की जानकारी

गौवर्धन पूजा के साथ मनाया जाएगा एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी उत्सव

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों के हित में केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ सभी किसानों को मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी का उत्सव गौवर्धन पूजा के साथ पूरे प्रदेश में मनाये जाने का निणज्य लिया है। साथ ही जन-प्रतिनिधियों और किसानों की उपस्थिति में कृषक कल्याण के फैसलों और किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार पूर्ण सजग है। किसान हितैषी फैसले निरंतर लिए जाएंगे, साथ ही किसानों के साथ नियमित संवाद भी होता रहेगा। बैठक में जानकारी दी गई की भारत सरकार की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटराइजेशन के अंतर्गत प्रदेश में 4536 पैक्स में कार्यवाही की गई है।

घर से ही करा सकेंगे ई-रजिस्ट्री-इस अवसर पर डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत ई-रजिस्ट्री की नवीन प्रणाली पर विकसित संपदा-2.0 पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। इस नवाचार का लाभ बड़ी संख्या में किसान वगज को प्राप्त होगा। इस नवाचार का लाभ बड़ी संख्या में किसान वगज को प्राप्त होगा। नवीन तकनीक पर आधारित संपदा-2.0 ऑनलाइन दस्तावेज पंजीयन एक क्रांतिकारी कदम है। किसान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पोर्टल और ऐप से नागरिकों को घर में ही यह सुविधा प्रदान किए जाने की शुरुआत और प्रदेश के सभी जिलों में जीआईएस लैब स्थापित करने का महत्वपूर्ण फैसला मध्यप्रदेश की नई पहचान बनाएगा।

बैठक में इन विषयों पर भी की गई चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों की चचाज में भूमि अधिग्रहण, बंटवारा, नामांतरण, इंद्राज दुरूस्ती, क्षेत्रीय स्तर पर फसल कटाई प्रयोग, सीमांकन कार्य के लिए मशीनों की संख्या में वृद्धि, सौ रुपए के स्टॉम्प पर रजिस्ट्रार द्वारा हकत्याग मान्य किए जाने आर आई एवं पटवारी के दायित्वों के स्वरूप, सहकारी संस्थाओं की भूमिका, खाद की व्यवस्था, अमानक दुग्ध के विक्रय पर नियंत्रण, तौल कांटों की व्यवस्था, महिला हम्मालों के लिए पृथक श्रेणी बनाने, प्रदेश की बड़ी कृषक उपज मंडियों में बड़े इलेक्ट्रानिक तौल कांटे की व्यवस्था, प्रदेश में कृषि आदान एवं उत्पाद में जल संसाधन विभाग की भूमिका एवं सहयोग के संबंध में भी चर्चा हुई।

योजना की अवधि 2026 तक बढ़ी

मध्यप्रदेश बना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में अग्रणी राज्य

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजनाके क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने इस निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय खाद्य प्र-संस्करण मंत्री चिराग पासवान का आभार व्यक्त किया है।

420 औद्योगिक इकाइयों की मिली मंजूरी

प्रमुख सचिव उद्यानिकी अनुपम राजन ने जानकारी दी कि योजना के तहत अब तक मध्यप्रदेश में 420 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृति दी गई है। यह संख्या एक रिकॉडज है और प्रदेश को योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

35प्रतिशत अनुदान और युवाओं को बढ़ावा- योजना के तहत निजी और समूह उद्यमियों को खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 35प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। इस प्रोत्साहन से राज्य के युवा कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र में अपनी स्वयं की औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

मध्यप्रदेश में पीएमएफएमई योजना 2020-21 से 2024-25 तक लागू की गई थी, जिसे अब एक साल और बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत 917 प्रकरणों में से 420 प्रकरणों को मंजूरी मिली है, जिससे राज्य इस योजना में देशभर में अग्रणी बन गया है।

केंद्र से सराहना मिली

अपर सचिव, केंद्रीय खाद्य प्र-संस्करण मंत्रालय, मिनहाज आलम ने प्रमुख सचिव अनुपम राजन और उनकी टीम के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें पत्र लिखा है, जिसमें योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशंसा की गई है।

तालाबों की लीज के लिए मछली पालकों से 25 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

रीवा। जागत गांव हमार

जिला पंचायत रीवा द्वारा दो बड़े तालाबों में मछली पालन के लिए लीज जारी करने के आवेदन मंगाए गए हैं। मछुआ सहकारी समिति अथवा समूह इसके लिए 25 अक्टूबर तक सहायक संचालक मछली पालन कार्यालय शिल्पी प्लाजा ए ब्लॉक में कार्यालयीन दिवस में आवेदन कर सकते हैं।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे ने बताया कि त्योंथर विकासखण्ड के लोनी तालाब क्षेत्रफल 129 हेक्टेयर तथा लीज राशि 19350 रुपए प्रतिवषज तथा हनुमना विकासखण्ड के गोरमा जलाशय क्षेत्रफल 463 हेक्टेयर लीज राशि 34725 रुपए निर्धारित है। इन दोनों तालाबों में मछली पालन के लिए 10 वर्ष के लिए पट्टे दिए जा रहे हैं। पट्टे देने में मछुआ समुदाय, आदिवासी मछली पालक, अनुसूचित जाति मछली पालक, पिछड़ावर्ग मछली पालक तथा सामान्य वर्ग के मछली

पालक पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों तथा स्वसहायता समूहों को को क्रमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन पत्र के साथ समिति के सदस्यों की प्रमाणित सूची, जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट तथा परिसमापन में नहीं होने से संबंधित उप पंजीयक सहकारी संस्था के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र के स्वीकार करने के संबंध में जिला पंचायत रीवा का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)